RNI No.: UPHIN/25/A1697
GARVI GUJARAT
गरवी गुजरात
गरवी गुजरात
लखनऊ से प्रकाशित दैनिक
वर्ष : 02
अंक : 007
दि. 07.05.2026, गुरुवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

'वियतनाम के साथ भारत ठोस परिणामों की ओर अग्रसर', तो लाम के साथ साझा प्रेस वार्ता में बोले पीएम मोदी

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने भारत यात्रा की शुरूआत बोधगया से की थी। यह हमारे दोनों देशों की आध्यात्मिक परंपराओं को दशार्ता है। भारत और वियतनाम की साझेदारी में विरासत और विकास का महत्व है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत वियतनाम के सहयोग से आसियान के साथ अपने संबंधों का विस्तार करेगा।

(जीएनएस)।

नई दिल्लीः भारत और वियतनाम ने अपने संबंधों को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के साथ वार्ता के बाद कहा कि वियतनाम के सहयोग से भारत आसियान के साथ अपने संबंधों को भी व्यापक बनाएगा। बुधवार को भारत और वियतनाम ने आर्थिक एवं रक्षा संबंधों को उल्लेखनीय रूप से विस्तार देने का संकल्प जताया।

वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम का भारत दौरा दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने वाला माना जा रहा है। यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, डिजिटल टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग तेजी से बढ़ रहा है।

नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों का हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए साझा दृष्टिकोण है और दोनों पक्ष कानून के शासन, शांति, स्थिरता और समृद्धि में अपना योगदान जारी रखेंगे।

हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर तक पहुंचेगा। भारत और वियतनाम का द्विपक्षीय व्यापार पिछले 1 दशक में दोगुना होकर 16 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। 2030 तक इसे 25 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने के लिए हमने आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए है। बहुत जल्द वियतनाम भारत के अंगूर और अनार का स्वाद लेगा।

प्रधानमंत्री मोदी-आतंकवाद के विरुद्ध भारत का साथ देने के लिए मोदी ने वियतनाम की सरकार का आभार जताते हुए कहा कि पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करने और आतंकवाद के विरुद्ध हमारे संघर्ष में साथ खड़े रहने के लिए हम वियतनाम के आभारी हैं। लैम ने मंगलवार को भारत की अपनी तीन दिवसीय यात्रा शुरू की। उनके साथ उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है। इस महीने राष्ट्रपति चुने जाने के बाद यह उनकी पहली राजकीय यात्रा है।

एक दिन पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम से मुलाकात की। उन्होंने दोनों देशों के बीच बहुआयामी और व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर विचार-विमर्श किया।

इससे पहले राष्ट्रपति तो लाम ने बिहार के महाबोधि मंदिर में पूजा-अर्चना की। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गयाजी पहुंचने पर वियतनाम के राष्ट्रपति का गर्मजोशी से स्वागत किया।

नेवी के लिए डीआरडीओ ने बनाई घातक मिसाइल

(जीएनएस)।

भारत ने हाल ही में ओडिशा तट से लंबी दूरी की हाइपरसोनिक एंटी-शिप मिसाइल छ्फ-अरँट की सफल टेस्टिंग की है। यह मिसाइल DRDO द्वारा बनाई गई है, जिसकी रेंज 1,500 किलोमीटर तक अपने टारगेट को हिट करने की है। ये मिसाइल भारत के लिए क्यों जरूरी थी, कैसे काम करती है और क्या है इसकी खासियत सब जानेंगे।

क्या खास है इस मिसाइल में?

LR-AShM एक टू-स्टेप वाली, सॉलिड फ्यूल पर चलने वाली हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल है, जो मैक 5 से लेकर मैक 10 तक की स्पीड बहुत कम समय में हासिल कर सकती है। यह कम ऊंचाई पर उड़ते हुए, सेमी-बैलिस्टिक ट्रैक पर स्किप करती है, जिससे दुश्मन के रडार इसे आसानी से पकड़ नहीं पाते। इसमें इंडियन मेड सेंसर लगे हैं जो लास्ट स्टेप में चलते हुए टारगेट, जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर, को भी सटीक ढंग से निशाना बना सकते हैं। इसकी टर्मिनल गाइडेंस और हाई-स्पीड मैन्युवरिंग (हवा में बार-बार घूमना या चक्कर खाना) इसे बेहद घातक बनाती है।

हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती मौजूदगी और पाकिस्तान के साथ सामरिक तनाव ने भारत को अपनी समुद्री ताकत बढ़ाने के लिए मजबूर किया। खासकर चीन की एयरक्राफ्ट कैरियर आधारित रणनीति को देखते हुए, भारत को ऐसी मिसाइल की जरूरत थी जो लंबी दूरी से दुश्मन के जहाजों को निशाना बना सके। छ्फ-अरँट इसी जरूरत का जवाब है, जो भारत की A2/AD (Anti-Access/Area Denial) क्षमता को मजबूत करती है, यानी दुश्मन को भारत के समुद्री क्षेत्र के करीब आने से रोकना।

इस मिसाइल का उपयोग युद्ध के दौरान दुश्मन के बड़े युद्धपोत, एयरक्राफ्ट कैरियर और नौसैनिक ठिकानों को नष्ट करने के लिए किया

जाएगा। यह खास तौर पर उन परिस्थितियों में अहम होगी जब दुश्मन समुद्र के रास्ते भारत के करीब आने की कोशिश करेगा। इसकी लंबी रेंज और हाइपरसोनिक स्पीड भारत को स्टैंड-ऑफ अटैक की क्षमता देती है, यानी बिना पास गए ही दुश्मन को खत्म करना।

इसे बनाने में कितना खर्च आया?

छ्फ-अरँट प्रोजेक्ट की सटीक लागत सार्वजनिक रूप से जारी नहीं की गई है। हालांकि, डिफेंस एक्सपर्ट का मानना है कि हाइपरसोनिक तकनीक के विकास में हजारों करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि इसमें एडवांस्ड मटेरियल, प्रोपल्शन और गाइडेंस सिस्टम शामिल होते हैं। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि यह पूरी तरह स्वदेशी तकनीक पर आधारित है, जिससे लंबे समय में लागत कम होती है।

चीन पाकिस्तान को कैसे करेगी काउंटर?

इस मिसाइल के आने से चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। चीन, जो हिंद महासागर में अपनी समुद्री ताकत बढ़ा रहा है, अब भारत की इस कैपेसिटी के कारण अपनी रणनीति पर दोबारा सोचने को मजबूर होगा। साथ ही, वहीं पाकिस्तान के लिए भी यह एक मजबूत संदेश है कि भारत अब समुद्री युद्ध में भी हाई-टेक और तेज प्रतिक्रिया देने में सक्षम है। छ्फ-अरँट की हाइपरसोनिक स्पीड और रडार से बचने की क्षमता इसे इंटरसेप्ट करना बेहद मुश्किल बनाती है, जिससे यह कैरियर किलर जैसी भूमिका निभा सकती है।

फ्रीड्रेल्ल्रीि ऋ्क्ष१ ङ्म४

क्१ल्ल ऋ्रू ल्ल ड्रँल्लं: वर के साथ चीन कर रहा बड़ा खेल, ट्रंप संग मुलाकात से पहले ईरान के साथ मीटिंग, क्या हुआ तय?

क्१ल्ल ऋ्रू ल्ल ड्रँल्लं: वर के साथ चीन कर रहा बड़ा खेल, ट्रंप संग मुलाकात से पहले ईरान के साथ

भीषण गर्मी से बड़ी राहत, सीएम गुप्ता ने 13 मोबाइल हीट रिलीफ यूनिट्स को दिखाई हरी झंडी

राजधानी दिल्ली में सूरज के तीखे तेवर और बढ़ते तापमान के बीच केजरीवाल सरकार ने आम जनमानस को राहत पहुंचाने के लिए एक

महत्वपूर्ण पहल की है। मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली सचिवालय से 13 मोबाइल हीट रिलीफ यूनिट्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह कदम विशेष रूप से सड़कों पर काम करने वाले मजदूरों, यात्रियों और खुले में रहने वाले लोगों को लू के घातक प्रभाव से बचाने के लिए उठाया गया है।

दिल्ली सरकार का यह प्रयास न केवल तत्काल चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करेगा, बल्कि भीषण गर्मी में डिहाइड्रेशन और हीटस्ट्रोक जैसी आपात स्थितियों को रोकने में भी सहायक सिद्ध होगा। मुख्यमंत्री ने इस दौरान जनता से अपील की कि वे स्वास्थ्य दिशा-निर्देशों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मोबाइल हीट रिलीफ यूनिट्स की प्रमुख सुविधाएं- ये चलती-फिरती राहत इकाइयां दिल्ली के विभिन्न व्यस्त इलाकों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में तैनात रहेंगी।

पीएम मोदी की लोकप्रियता असाधारण, उनके आसपास विश्व का कोई नेता नहीं एरिक सोल्हेम

उन्होंने ट्रंप सहित विश्व भर के नेताओं से तुलना करते हुए कहा 'मोदी ने अपनी मेहनत और देश के विकास के विजन के दम पर जितनी लोकप्रियता हासिल की है, उसके आसपास भी कोई भी नहीं पहुंचता'।

(जीएनएस)।

नई दिल्ली, नॉर्वे के पूर्व जलवायु और पर्यावरण मंत्री एरिक सोल्हेम ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सहित विश्व भर के नेताओं से तुलना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी मेहनत और देश के विकास के विजन के दम पर जितनी लोकप्रियता हासिल की है, उसके आसपास भी कोई भी नहीं पहुंचता।

सोल्हेम ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत करते हुए कहा कि लोकतंत्र में किसी नेता के लिए लंबे समय तक इतनी मजबूत जनसमर्थन बनाए रखना बहुत ही दुर्लभ होता है।

उन्होंने कहा, 'प्रधानमंत्री मोदी

भारत में बेहद लोकप्रिय हैं। मेरा मानना है कि लोकतंत्र में ऐसा बहुत कम ही होता है कि कोई नेता इतने लंबे समय तक इतना बड़ा समर्थन जुटा पाए, जैसा पीएम मोदी ने किया है।'

सोल्हेम ने आगे कहा, 'शायद 1950 के दशक में जब यूरोप में लगातार तेज विकास हो रहा था, तब वहां के नेता ऐसा सपना देख सकते थे, लेकिन आज के समय में यह बहुत ही खास और अलग बात है।'

उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय आई है, जब अमेरिकी डेटा एनालिटिक्स कंपनी 'मॉर्निंग कंसल्ट' के एक सर्वे में प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता बताया गया है।

2 से 8 मार्च के बीच किए गए इस सर्वे के मुताबिक, एनालिटिक्स फर्म ने कहा कि पीएम मोदी 68 प्रतिशत की मजबूत अप्रूवल रेटिंग के साथ दुनिया के बाकी नेताओं से काफी आगे हैं।

सोल्हेम ने कहा, 'फिलहाल मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई भी नेता अपने देश में प्रधानमंत्री मोदी जितना लोकप्रिय है।'

उन्होंने कहा, 'हो सकता है कुछ छोटे देशों में ऐसा कोई नेता हो, लेकिन किसी बड़े देश में आपको इतना लोकप्रिय नेता नहीं मिलेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप भी पीएम मोदी की लोकप्रियता के आसपास नहीं हैं, और न ही कोई यूरोपीय नेता। मेरे हिसाब से वह सच में एक विश्व नेता हैं।'

सोल्हेम ने यह भी कहा कि पीएम मोदी की निजी जिंदगी का सफर भी उनकी लोकप्रियता की बड़ी वजह है। उन्होंने कहा कि गुजरात में एक साधारण परिवार से निकलकर, जहां उनका परिवार एक छोटे रेलवे स्टेशन पर चाय बेचता था, वहां से दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में शामिल होना, यह बहुत ही प्रेरणादायक है। जब हमने अपना पहला गणतंत्र दिवस मनाया

प्रयागराजः सीएम योगी ने किया रक्षा प्रदर्शनी का किया अवलोकन, बोले- हमारी उदारता को न समझें कमजोरी

प्रदर्शनी में आधुनिक युद्ध की जरूरतों के अनुरूप विकसित तकनीकों और उपकरणों ने भारत की शक्ति दिखाई गई.

(जीएनएस)।

नॉर्थ टेक सिम्पोजियम-2026 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डिफेंस एग्जीबिशन का अवलोकन करते हुए देश की उभरती स्वदेशी रक्षा क्षमताओं की सराहना की. तीन दिवसीय इस आयोजन में आधुनिक युद्ध की जरूरतों के अनुरूप विकसित अत्याधुनिक तकनीकों और उपकरणों का व्यापक प्रदर्शन किया गया, जिसमें सेना, उद्योग और स्टार्टअप्स की सहभागिता स्पष्ट रूप से दिखाई दी.

प्रदर्शनी के दौरान मुख्यमंत्री ने

बुलेटप्रूफ जैकेट, टैक्टिकल गियर, अत्याधुनिक हेलमेट और मल्टी-टेरेन ऑपरेशंस के लिए विकसित सैन्य उपकरणों का बारीकी से निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने विशेषज्ञों से तकनीकी विशेषताओं की जानकारी ली और उत्पादों की उपयोगिता पर चर्चा की. विशेष रूप से 'हेड-टू-बूट' सुरक्षा प्रणाली, अत्यधिक विषम तापमान में पहने जाने वाले कपड़े और मॉड्यूलर प्रोटेक्शन सिस्टम जैसे इनोवेशन आकर्षण का केंद्र रहे.

सिम्पोजियम में प्रदर्शित तकनीकों में ड्रोन, स्मार्ट सर्विलांस सिस्टम, कम्युनिकेशन उपकरण और भविष्य के युद्धक्षेत्र के लिए विकसित एआई आधारित समाधान भी शामिल रहे. यह आयोजन इस बात का संकेत है कि भारत अब पारंपरिक युद्ध से आगे बढ़कर मल्टी-डोमेन वॉरफेयर यानी साइबर, स्पेस और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम में भी अपनी तैयारी मजबूत कर रहा है. प्रदर्शनी में बड़ी संख्या में एमएसएमई, स्टार्टअप्स और रक्षा कंपनियों की भागीदारी ने 'मेक इन इंडिया' और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को मजबूती दी है.

महाराष्ट्र सरकार कर्मचारियों का करवा रही हिंदी नॉलेज टेस्ट, उद्धव शिवसेना ने हिंदी थोपने का लगाया आरोप

(जीएनएस)।

महाराष्ट्र सरकार द्वारा कर्मचारियों के लिए हिंदी नॉलेज एग्जाम आयोजित की जा रही है। फडणवीस सरकार की हालिया अधिसूचना ने राज्य में भाषा प्राथमिकताओं को लेकर एक नई राजनीतिक व सांस्कृतिक बहस छेड़ दी है। इसे 'हिंदी थोपने' का प्रयास बताया जा रहा है।

महाराष्ट्र के भाषा विभाग ने मुंबई, पुणे, नागपुर और छत्रपति संभाजीनगर के संभागीय केंद्रों पर 28 जून 2026 को राजपत्रित व गैर-राजपत्रित अधिकारियों के लिए हिंदी परीक्षा आयोजित की जाएंगी।

हालांकि ऐसी परीक्षाएं पूर्व में भी हुई हैं, लेकिन इस बार इस निर्णय की राजनीतिक दलों और भाषा कार्यकताओं ने कड़ी आलोचना की है। शिवसेना (यूबीटी) ने इस फैसले पर कड़ा विरोध जताया।

शिवसेना (यूबीटी) ने पूछा, "राज्य कर्मचारियों पर हिंदी थोपने की कोशिश से आखिर किसके हितों की पूर्ति हो रही है?" पार्टी ने मराठी की आधिकारिक भाषा वाले राज्य में हिंदी को बढ़ावा देने पर सवाल उठाए।

पार्टी का तर्क है कि मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलने के बावजूद सरकारी कर्मचारियों पर हिंदी थोपना विरोधाभासी है। उनका कहना है कि महाराष्ट्र की पहचान मराठी भाषा और संस्कृति में गहराई से निहित है।

मराठी अभ्यास केंद्र के अध्यक्ष डॉ. दीपक पवार ने भी आलोचना की। उन्होंने कहा, जब प्रशासनिक संवाद पहले से ही मराठी में होता है, तो कर्मचारियों की हिंदी दक्षता जांचने का क्या औचित्य है?

डॉ. पवार ने जोर दिया कि हिंदी न महाराष्ट्र की आधिकारिक भाषा है और न ही दैनिक प्रशासन के लिए आवश्यक। उन्होंने गैर-हिंदी भाषी राज्यों जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक या गुजरात में ऐसे इम्तिहानों पर भी सवाल उठाया। इस कदम को अनावश्यक बताते हुए डॉ. पवार ने आरोप लगाया कि यह मराठी को कमजोर करता है और प्रशासनिक संसाधनों की बबार्दी है। उन्होंने सरकार से प्रस्तावित परीक्षाएं तत्काल रद्द करने और फैसले पर पुनर्विचार न होने पर विरोध-प्रदर्शनों की चेतावनी दी।

सोशल मीडिया पर घिरे सीएम और डिप्‍टी सीएम

यह विवाद तेजी से सोशल मीडिया पर फैला है, जहां मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री सहित कई राजनीतिक नेताओं को स्पष्टीकरण की मांग वाले पोस्ट में टैग किया गया है।

सम्राट कैबिनेट विस्तार से पहले पटना में पीएम मोदी का रोड शो, नितिन-नीतीश और अमित शाह करेंगे शिरकत

(जीएनएस)।

पटना। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल विस्तार कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को पटना दौरे पर रहेंगे। इस दौरान राजधानी में उनका भव्य रोड शो आयोजित किया जाएगा, जिसे लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई हैं।

बड़े नेताओं की मौजूदगी से कार्यक्रम को मिलेगा खास महत्व

प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नितिन नवीन भी मौजूद रहेंगे।

इन दिग्गज नेताओं की उपस्थिति से कार्यक्रम का राजनीतिक महत्व और बढ़ गया है।

एयरपोर्ट से गांधी मैदान तक तय किया गया रोड शो का रूट

रोड शो का रूट पटना एयरपोर्ट से

शुरू होकर हार्डिंग रोड, वीरचंद्र पटेल पथ, आयकर चौराहा होते हुए गांधी मैदान तक जाएगा।

इस पूरे मार्ग पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं और बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की संभावना है।

छह महीने बाद पटना आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग छह महीने बाद पटना पहुंच रहे हैं। इससे पहले वे 20 नवंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने गांधी मैदान आए थे।

प्रधानमंत्री का पटना पहुंचने का समय सुबह 10:00 बजे निर्धारित है। इसके बाद दोपहर 12:05 बजे से 1:30 बजे तक रोड शो आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के अनुसार वे करीब 12 बजे गांधी मैदान पहुंचेंगे, जहां आगे के आयोजन होंगे।

प्रशासन अलर्ट, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर पटना पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। रोड शो के रूट पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं, साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था में भी बदलाव किया जाएगा ताकि कार्यक्रम सुचारु रूप से संपन्न हो सके।

सम्पादकीय

पेंटागन की आलोचना

पूर्व शीर्ष सैन्य वकील समेत अमेरिका के पांच पूर्व अधिकारियों ने इस साल की शुरूआत में ईंरान के एक स्वूल पर हुए घातक हमले में संभावित अमेरिकी भूमिका को स्वीकार न करने पर पेंटागन (अमेरिकी रक्षा मंत्रालय) की आलोचना की है। इनमें से वुछ ने कहा कि इतने लंबे समय बाद भी हमले की बुनियादी जानकारी तक जारी न करना बेहद असामान्य है। ईंरानी अधिकारियों के मुताबिक 28 फरवरी को अमेरिका-इजरायल युद्ध की शुरूआती कार्रवाई के दौरान मिनाब में एक प्राइमरी स्वूल पर मिसाइल गिरी। जिसमें करीब 110 बच्चे समेत 168 लोगों की मौत हुईं। इसके बाद बीते दो महीनों में पेंटागन ने सिर्प इतना कहा है कि इस घटना की जांच जारी है। मार्च की शुरूआत में अमेरिकी मीडिया ने खबर दी थी कि अमेरिकी सैन्य जांचकताओं का मानना है कि शायद अमेरिकी बल अनजाने में स्वूल पर हमले के लिए जिम्मेदार थे, लेकिन वे अंतिम निष्कर्ष तक नहीं पहुंचे थे। बीबीसी ने इस हमले की पारदर्शिता की कमी के आरोपों पर कईं सवाल पूछे, जिस पर पेंटागन के एक अधिकारी ने कहा, इस घटना की जांच जारी है। लेफ्टिनेंट कर्नल रेचल ईं वेनलैंडिंगम कहती हैं कि अमेरिका की मौजूदा स्थिति सामान्य प्रतिव्रिया से साफ तौर पर अलग है। वेनलैंडिंगम अमेरिकी वायुसेना में जज एडवोकेट जनरल रह चुकी हैं। उन्होंने बताया कि पिछली सरकारों ने कम से कम युद्ध कानून के प्रति निष्ठा और प्रतिबद्धता दिखाईं थी।

मौजूदा प्रशासन के बयानों में जबावदेही की प्रतिबद्धता गायब है। सबसे अहम यह सुनिश्चित करना भी कि ऐसा दोबारा न हो। राष्ट्रपति ट्रंप ने 7 मार्च को कहा था कि उनके विचार में मिनाब हमले के लिए ईंरान जिम्मेदार है, लेकिन उन्होंने कोईं सुबूत नहीं दिया। वुछ दिन बाद जब उनसे मिनाब स्वूल के पास सैन्य अड्डे पर अमेरिकी टॉमहॉक मिसाइल गिरने का वीडियो दिखाए जाने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहाः मैंने यह नहीं देखा। साथ ही ट्रंप ने बिना किसी सुबूत दावा किया कि ईंरान के पास भी टॉमहॉक मिसाइलें थीं। 11 मार्च को जब उनसे उन खबरों के बारे में पूछा गया जिसमें कहा गया था कि शुरूआती सैन्य जांच में पाया गया कि अमेरिका ने स्वूल पर हमला किया था तो ट्रंप ने कहा मुझे इसके बारे में नहीं पता। अमेरिका के रक्षामंत्री पीट हेगसेथ से 4 मार्च को बीबीसी ने इस हमले पर सवाल किया था तो उन्होंने कहा, मैं सिर्प इतना कह सकता हूं कि हम इसकी जांच कर रहे हैं। यही नहीं अमेरिकी रक्षा विभाग ने इस हमले पर कईं सवालों के जवाब देने से इंकार कर दिया। पिछले महीने बीबीसी ने स्वतंत्र रूप से हमले की वीडियो की पुष्टि की थी जिसमें स्वूल के पास ईंरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (आईंआरजीसी) के अड्डे पर अमेरिकी टॉमहॉक मिसाइल गिरती दिख रही थी। पेंटागन के एक वरिष्ठ पूर्व सलाहकार वेस ब्रायंट ने बीबीसी से कहा कि शुरूआती सैन्य जांच आमतौर पर दो बातें तय करने के लिए होती है। पहली, क्या नागरिक क्षति वास्तव में हुईं? दूसरी क्या उस समय अमेरिका उस इलाके में सव्रिय था या नहीं? जब दोनों शर्ते पूरी हो जाती हैं, तभी औपचारिक जांच शुरू की जाती है। प्रव्रिया के लिहाज से यह और भी साफ संकेत देता है कि वे पहले से जानते हैं कि वह अमेरिका की वजह से हुआ नहीं तो वे जांच नहीं कर रहे होते। वे बस इसे स्वीकार नहीं करना चाहते या इस पर बोलना नहीं चाहते। पिछले साल अमेरिका के रक्षा विभाग ने नौकरियों की कटौती की थी, उसमें ब्रायंट भी शामिल थे।

प. बंगाल में एक अहम जीत के बाद भी वहां कि बजाये पहले पटना क्यों जा रहे हैं पीएम, है बड़ी वजह

(जीएनएस)।

9 मई को बंगाल में भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण होना है, लेकिन उससे पहले 7 मई को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक जीत के बाद भाजपा के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को है। जबकि बिहार में भाजपा के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल का विस्तार 7 मई को है। उपलब्धि के लिहाज से भाजपा के लिए पश्चिम बंगाल का कार्यक्रम ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन इसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पहले बिहार आ रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार, नवनिर्वाचित सरकार की एक सामान्य प्रक्रिया है। फिर भी नरेन्द्र मोदी और अमित शाह इस कार्यक्रम को बहुत अधिक महत्व दे रहे हैं। आखिर वजह क्या है? क्या इसमें कोई राजनीतिक संकेत छिपा है?

ब्रिटिश काल में पश्चिम बंगाल, बिहार और ओडिशा बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा थे। उस समय यह भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। जब बिहार, बंगाल और ओडिशा एक प्रांत थे तब भौगोलिक और सांस्कृतिक आधार पर उन्हें 'अंग-बंग-कलिंग' कहा जाता था। इस भौगोलिक शब्दावली की 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा में बहुत चर्चा रही। अंग मतलब आधुनिक बिहार का भागलपुर क्षेत्र जो पश्चिम बंगाल के नजदीक है। बंग का मतलब पश्चिम बंगाल और कलिंग का मतलब ओडिशा।

अब इस भौगोलिक त्रिकोण में भाजपा के मुख्यमंत्री का चीर प्रशिक्षित सपना पूरा हो गया। लेकिन बिहार में यह सपना अभी भी अधूरा है। बिहार में भाजपा के मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन उनका वजूद जदयू के समर्थन पर निर्भर है। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भाजपा की पूर्ण बहुमत वाली सरकार है। लेकिन बिहार में वह गठबंधन की सरकार चला रही है। इसकी कसक उसे है।

7 मई को जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अमित शाह पटना आएंगे तब अपने साथ पश्चिम बंगाल की रिकॉर्डतोड़ जीत की धमक भी लाएंगे। बिहार की फिजा में पश्चिम बंगाल की जीत की खुशबू होगी, जो यहां के लोगों को बहुत सिद्दत से महसूस होगी। पटना के गांधी मैदान से एक ध्वनि गूंजेगी, जिसके शब्द होंगे- 'अगर बंगाल का कठिन रण जीत लिया तो बिहार भी जीतेंगे', बिहार विधानसभा चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, गंगा जी पटना से बहते होते हुए पश्चिम बंगाल जाती हैं। अब जब पश्चिम बंगाल जीत लिया तो भाजपा के नेता कहेंगे- 'बंगाल की पुरवैया बयार अब बिहार आएगी।'

बंगाल की जीत ने भाजपा के आत्मविश्वास को बुलंदियों पर पहुंचा दिया है। यह सच है कि उसने इस सियासी जंग में वह फतह पायी है, जिसे जीतना नामुमकिन माना जाता था। जब बंगाल जीत लिया तो बिहार क्यों नहीं जीता जा सकता? बिहार में तो वह नवम्बर 2005 (बीच में कुछ समय छोड़ कर) से सत्ता में है। इतने साल के शासन काल में तो पार्टी ने अपना एक मजबूत आधार बना लिया है।

बंगाल की तुलना में तो बिहार को अकेले जीतना ज्यादा आसान है। लेकिन बिहार की राजनीति में अलग तरह की चुनौतियां हैं। यहां नीतीश कुमार और लालू यादव के रूप में दो प्रमुख राजनीतिक शक्तियां हैं, जो अभी भी बहुत प्रभावी हैं। बंगाल में तो भाजपा को सिर्फ ममता बनर्जी को मात देनी थी। वाम दल और कांग्रेस पहले ही खत्म हो गये थे। लेकिन बिहार में भाजपा को दो 'किले' (नीतीश कुमार और लालू यादव) ढहाने होंगे। यह आसान नहीं है।

आसान तो ममता बनर्जी के भी सत्ता से बेदखल करना नहीं था। लेकिन वे न केवल हारीं बल्कि बुरी तरह हारीं। 2021 में 215 सीटें जीतने वाली ममता बनर्जी 2026 में 80 पर कैसे सिमट गयीं ? दरअसल ममता बनर्जी की हार से एक बात साफ हो गयी कि अब देश में तुष्टिकरण की राजनीति नहीं चलेगी। आप किसी वर्ग विशेष के वोट लेने के लिए अधिसंख्य लोगों के हितों की बलि नहीं चढ़ा सकते। अगर कोई नेता अल्पसंख्यकों के प्रति जरूरत से ज्यादा झुकाव दिखाएगा तो इसकी प्रतिक्रिया में बहुसंख्यक लोगों का बहुत तेज ध्रुवीकरण होगा। अगर ऐसा हुआ तो जाति से जुड़े सारे समीकरण ध्वस्त हो जाएंगे। पश्चिम बंगाल के उदाहरण से समझा जा सकता है। पश्चिम बंगाल में जंगल महल के नाम से जो भौगोलिक इलाका है, उसमें चार जिले आते हैं- पुरुलिया, झाड़ग्राम, बांकुड़ा और पश्चिमी मेदिनीपुर। यह इलाका जंगलों से घिरा हुआ है और यहां अधिकतर आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं। ममता बनर्जी की तुष्टिकरण की बढ़ती नीति से इन चार जिलों में भी गहरी नाराजगी थी। यहां वोटरों ने जाति- वर्ग से ऊपर उठ कर ममता बनर्जी को हराने के लिए पूरी ताकत लगा दी। यह चुनाव परिणामों से साबित होता है।

भाजपा ने पुरुलिया की सभी 9 सीटें और झाड़ग्राम की सभी 4 सीटें जीत लीं। बांकुड़ा की 12 में 11 सीटें और पश्चिमी मेदिनीपुर की 15 में से 13 सीटें भाजपा की झोली में गिरीं। यानी अब देश में वही राजनीति चलेगी जो सभी धर्मों और जाति को एक साथ लेकर चल सके।

जानकारों का कहना है कि ममता बनर्जी की राजनीति खास ढर्रे पर चल रही थी। वे समझती थीं कि 30 फीसदी (मुस्लिम) वोट तो उनका पक्का है। अगर 70 फीसदी (हिंदू) वोटों में से 20 फीसदी वोट भी बांट लिया जाए तो जीत पक्की है। लेकिन इस बार 70 फीसदी एकजुट हो गया और ममता बनर्जी हार गयीं।

अगर बिहार में नीतीश कुमार और लालू यादव ममता बनर्जी वाली गलती दोहराएंगे तो भाजपा के लिए यहां भी मौका बन जाएगा। इसलिए भाजपा के नेता पश्चिम बंगाल से आने वाली हवा के लिए बिहार की खिड़की खोल कर रखना चाहते हैं।

सीएम योगी बोले- कीबोर्ड और डेटा अब सेना के नए हथियार, यूपी बनेगा देश की रक्षा का अभेद्य कवच

(जीएनएस)।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को प्रयागराज में आयोजित रक्षा त्रिवेणी संगम (नॉर्थ टेक सिंपोजियम-2026) के समापन समारोह में भविष्य के युद्धों और भारत की रक्षा तैयारियों का एक व्यापक खाका खींचा। उन्होंने स्पष्ट किया कि आधुनिक युद्ध अब केवल जल, थल और नभ की सीमाओं तक सीमित नहीं रह गया है। आज के युग में कीबोर्ड, सैटेलाइट और डेटा नेटवर्क उतने ही प्रभावी हथियार बन चुके हैं जितने कि पारंपरिक मिसाइलें और टैंक। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि

साइबर, स्पेस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम अब नए रणक्षेत्र हैं, जहां दुश्मन के संचार और पावर ग्रिड को बाधित करना ही जीत की नई रणनीति है।

भारतीय सेना के उत्तरी तथा मध्य कमान तथा भारतीय रक्षा निमार्ता सोसायटी की ओर से न्यू कैंट स्थित कोबरा ऑडिटोरियम में तीन दिवसीय सिंपोजियम के अंतिम दिन मुख्यमंत्री ने यूपी की रक्षा क्षेत्र में बढ़ती ताकत का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य का डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जल्द ही भारत की सैन्य शक्ति का मुख्य आधार बनेगा।

उन्होंने बताया कि राज्य के छह नोड्स लखनऊ, कानपुर, झांसी, आगरा, अलीगढ़ और चित्रकूट में 35,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्तावों पर तेजी से काम हो रहा है। अलीगढ़ जहां छोटे हथियारों का केंद्र बना है, वहीं कानपुर में मिसाइल और गोला-बारूद का निर्माण हो रहा है। लखनऊ और झांसी में ब्रह्मोस जैसी आधुनिक मिसाइलों के निर्माण से देश की सैन्य क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि होगी।

योगी आदित्यनाथ ने रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता पर गर्व व्यक्त करते हुए कहा कि कुछ साल पहले तक हमारा रक्षा निर्यात मात्र 600 करोड़ रुपये था, जो आज बढ़कर 50 हजार करोड़ रुपये के स्तर तक पहुंचने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अपनी 56 प्रतिशत युवा कार्यकुशल आबादी और 96 लाख एमएसएमई इकाइयों के साथ रक्षा क्षेत्र के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम प्रदान कर रहा है।

मुख्यमंत्री ने नेशन फर्स्ट के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि हर नागरिक के लिए राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए, क्योंकि मजबूत राष्ट्र ही सुरक्षित भविष्य की गारंटी है। सीएम ने वहां लगी रक्षा प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। इस अवसर पर लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद्य सेनगुप्ता, लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, उत्तर प्रदेश सरकार में औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, लेफ्टिनेंट जनरल वी. हरिहरन, उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण, एसआईडीएम के वाइस प्रेसिडेंट नीरज गुप्ता, आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर ए.के. घोष के साथ ही सेना के कई वरिष्ठ अधिकारीगण और स्टेकहोल्डर्स उपस्थित रहे।

सीएम ने कहा कि रक्षा विनिर्माण में उत्तर प्रदेश की भूमिका अब केवल पुर्जे बनाने तक सीमित नहीं है। कानपुर नोड में जहां बुलेटप्रूफ जैकेट और डिफेंस टेक्सटाइल का उत्पादन हो रहा है तो वहीं आईआईटी कानपुर के सहयोग से विकसित ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भविष्य की मानवरहित युद्ध प्रणाली के लिए स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार कर रहा है। सरकार की डिफेंस एवं एयरोस्पेस पॉलिसी ने निवेशकों के लिए उत्तर प्रदेश को देश का सबसे पसंदीदा गंतव्य बना दिया है।

लिव-इन पार्टनर ने स्टार एक्ट्रेस को 'बाजार' में बेचा, पति ने लगाई नशे की लत, 34 साल में मिली ऐसी दर्दनाक मौत

(जीएनएस)।

हिंदी सिनेमा में कई ऐसी कहानियां हैं, जहां सफलता की ऊंचाइयों के साथ दर्द की गहरी खाई भी जुड़ी होती है। बॉलीवुड की लिजेंड्री एक्ट्रेस रह चुकीं मीना कुमारी को ट्रेजेडी क्वीन कहा गया लेकिन एक और अभिनेत्री की जिंदगी भी कुछ ऐसी ही त्रासदी से भरी रही थी।

ये कहानी है 60 और 70 के दशक की खूबसूरत एक्ट्रेस विमी की, जिन्होंने बहुत कम समय में शोहरत हासिल की लेकिन उनका अंत बेहद दर्दनाक रहा। उनकी दर्दनाक कहानी ने सबको झकझोर कर रख दिया था।

-आपको बता दें कि विमी ने हिंदी सिनेमा में कदम रखते ही दर्शकों का दिल जीत लिया था। उनकी पहली फिल्म 'हमराज' सुपरहिट साबित हुई थी, जिसमें उन्होंने सुनील दत्त, शशि कपूर और राज कुमार जैसे बड़े स्टार्स के साथ काम किया था।

-इस फिल्म के बाद विमी इंडस्ट्री की नई सेंसेशन बन गई थीं। इसके बाद वह निमार्ता-निर्देशकों की पहली पसंद बनती चली गईं। 60 के दशक में विमी एकमात्र ऐसी एक्ट्रेस थीं जो एक फिल्म के लिए 3 लाख रुपए की फीस लेती थीं।

-विमी एक संपन्न परिवार से ताल्लुक रखती थीं। वह काफी पढ़ी-लिखी थीं, कला और संगीत में गहरी रुचि रखती थीं और उनकी आवाज भी बहुत मधुर थी लेकिन परिवार को उनका फिल्मों में आना मंजूर नहीं था। अपने सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने घर-परिवार से दूरी बना ली और मुंबई का रुख किया था।

-कम उम्र में विमी की शादी एक बिजनेसमैन परिवार में हुई थी और उनके दो बच्चे भी थे। बावजूद इसके, उन्होंने अपने करियर को प्राथमिकता दी थी, जिसका असर उनके निजी जीवन पर धीरे-धीरे दिखने लगा था।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक पार्टी के दौरान विमी की मुलाकात मशहूर संगीतकार रवि से हुई थी। उनकी खूबसूरती और व्यक्तित्व से प्रभावित होकर रवि ने उन्हें फिल्मों में आने की सलाह दी थी। इसके बाद संगीतकार रवि ने ही विमी की मुलाकात फिल्ममेकर बीआर चोपड़ा से कराई थी, जिन्होंने उन्हें 'हमराज' मूवी में मौका देकर स्टार बना दिया था।

हालांकि इस फैसले की कीमत विमी को अपने परिवार से दूरी और संपत्ति से बेदखल होने, के रूप में चुकानी पड़ी थी। इसके बाद अचानक घर की जिम्मेदारियां भी उनके कंधों पर आ गई थीं। दरअसल फिल्मों में काम करने को लेकर विमी के ससुराल वालों ने उन्हें और उनके पति, दोनों को घर और संपत्ति से बेदखल कर दिया था। इसके बाद घर चलाने की जिम्मेदारी विमी पर आ गई थी।

मुंबई इंडियंस में मची खलबली, आरसीबी के खिलाफ मैच के लिए रायपुर नहीं पहुंचे कप्तान हार्दिक पांड्या

(जीएनएस)।

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के बीच सीजन में मुंबई इंडियंस के खेमे से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने क्रिकेट जगत में चचाओं का बाजार गर्म कर दिया है। टीम के आधिकारिक कप्तान हार्दिक पांड्या बुधवार को अपनी टीम के साथ रायपुर नहीं पहुंचे हैं, जहां मुंबई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ अपना अगला महत्वपूर्ण मुकाबला खेलना है।

क्रिकबज के अनुसार मुंबई हवाई अड्डे पर टीम के अन्य खिलाड़ियों के साथ हार्दिक की अनुपस्थिति ने उन अटकलों को और हवा दे दी है जो पिछले कुछ हफ्तों से टीम के अंदरूनी कलह और नेतृत्व परिवर्तन की ओर इशारा कर रही हैं।

फ्रेंचाइजी की ओर से पिछली बार यह जानकारी दी गई थी कि हार्दिक पांड्या पीठ में खिंचाव यानी बैक स्पैस्म से जूझ रहे हैं और इसी वजह से उन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ पिछला मैच नहीं खेला था। लेकिन अब जब टीम रायपुर के लिए रवाना हुई और कप्तान वहां भी दिखाई नहीं दिए, तो सवाल यह उठने लगा है कि क्या यह सिर्फ एक शारीरिक चोट है या फिर कहानी कुछ और है।

खेल के जानकारों का मानना है कि अगर यह सिर्फ एक मामूली खिंचाव होता तो हार्दिक को टीम के साथ यात्रा करने और डगआउट में खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए थी। हार्दिक की गैरमौजूदगी में सूर्यकुमार यादव टीम की कमान संभाल रहे हैं और दिलचस्प बात यह है कि उनकी कप्तानी में मुंबई ने लखनऊ के खिलाफ एक शानदार जीत दर्ज की।

10 मई को होने वाले मुकाबले से पहले मुंबई इंडियंस के फैंस इस उम्मीद में हैं कि कप्तान सीधे रायपुर पहुंचेंगे, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई है। टीम फिलहाल अंक तालिका में नौवें स्थान पर संघर्ष कर रही है और प्लेऑफ की राह उनके लिए लगभग नामुमकिन नजर आ रही है।

ऐसे नाजुक मोड़ पर कप्तान का टीम के साथ न होना यह संकेत देता है कि मुंबई इंडियंस के ड्रेसिंग रूम में सब कुछ ठीक नहीं है। आने वाले कुछ दिन यह साफ कर देंगे कि हार्दिक पांड्या की यह दूरी केवल फिटनेस से जुड़ी है या फिर मुंबई की टीम में किसी बड़े बदलाव की कहानी लिखी जा चुकी है।

ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों को पाक फौज का था सपोर्ट, नेता ने खुद कबूला, अब हुई किरकरी

(जीएनएस)।

7 मई को ऑपरेशन सिंदूर को एक साल पूरा हो जाएगा। इसी बीच पाकिस्तान से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने भारत और दुनिया के उन तमाम देशों के दावे सच साबित कर दिए जिसमें पाक द्वारा आतंकियों को पालने की बात कही जाती है। दरअसल एक पाकिस्तानी नेता के बयान ने सेना और आतंकियों के रिश्तों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या है पूरा मामला, डिटेल में समझते हैं।

पाकिस्तान नजरियाती पार्टी के अध्यक्ष शाहीर सियालवी ने रावलपिंडी में लश्कर-ए-तैयबा के एक कार्यक्रम में बड़ा खुलासा किया। शाहीर ने कहा कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों को पाकिस्तानी सेना ने सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी। इसमें वर्दी पहने सैनिकों द्वारा ताबूत उठाना और सैन्य अंतिम संस्कार शामिल था।

शाहीर ने कहा कि "हाफिज सईद, मसूद अजहर और सैयद सलाउद्दी के मुजाहिदीनों को इन लोगों राज्य अपना बताए। अगर चे ग्वेरा, फिदेल कास्त्रो, नेल्सन मंडेला, सुभाष चंद्र बोस और

भगत सिंह को दुनिया फ्रीडम फाइटर कहती है तो इन्हें आतंकवादी क्यों कहा जाता है। अटैक मुरीदके और बहावलपुर में हुआ था लेकिन पाक फौज ने पहली बार तय किया कि इनके जनाजे पाक फौज मौलाना पढ़ाएगा ताकि दुनिया को बता सकें ये आतंकवादी नहीं फ्रीडम फाइटर थे।"

शाहीर ये बताना भूल गया कि सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह अपने देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे। उन्होंने कभी किसी मासूम की जान नहीं ली। कभी किसी शहर में सिर्फ इसलिए दहशत नहीं फैलाई क्योंकि वहां दूसरे धर्म के लोगों ज्यादा तादाद में रहते हैं।

अब इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में सियालवी के साथ मुजम्मिल हाशमी भी बैठे दिखाई देता है, जो हाफि ज सईद का करीबी है और कई आतंकी वारदातों में भी शामिल रहा है।

पाकिस्तानी सरकार और आर्मी दोनों आतंकियों से दिखाने के लिए ही सही पर दूरी बनाता है। यहां तक कि कई मौकों पर उसने हाफिज सईद को दिखावे के लिए जेल में भी डाला है। लेकिन शाहीर ने पाकिस्तानी सरकार और फौज दोनों की पोल खोल दी। साथ ही सियालवी के इस बयान ने पाकिस्तान के उस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें वह कहता है कि उसके यहां स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट काम करते हैं।

सियालवी ने यह भी कहा कि पाकिस्तानी सेना ने हाफि ज सईद और मसूद अजहर के लिए सीजफायर का उल्लंघन किया और भारत के खिलाफ कार्रवाई की। उन्होंने दावा किया कि सेना ने पहली बार इन लोगों के लिए सीधे तौर पर लड़ाई लड़ी।

इससे पहले भी मसूद इलियास कश्मीरी ने एक वायरल वीडियो में कहा था कि पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन में मारे गए लोगों के अंतिम संस्कार में अपने जनरल भेजे थे। जो बताता है कि पाकिस्तानी फौज और आतंकी अलग-अलग नहीं है।

भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद 'ऑपरेशन सिंदूर' शुरू किया था। इसका लक्ष्य पाकिस्तान और ढङ्कङ्ख में मौजूद आतंकी ढांचे को नष्ट करना था। इस ऑपरेशन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ समय के लिए सैन्य तनाव भी बढ़ गया

क्या है पिंक प्रॉमिस मैच? आईपीएल में 9 मई को खेला जाएगा मुकाबला, राजस्थान और गुजरात में टक्कर

(जीएनएस)।

राजस्थान रॉयल्स ने घोषणा की है कि 9 मई को गुजरात टाइटंस के खिलाफ होने वाला घरेलू मैच फ्रेंचाइजी का 'पिंक प्रॉमिस' मैच होगा। यह एक विशेष मुकाबला है जो अब अपने तीसरे वर्ष में प्रवेश कर चुका है। रॉयल राजस्थान फाउंडेशन (RRF) द्वारा संचालित यह पहल महिलाओं के नेतृत्व वाले परिवर्तन की दिशा में राजस्थान रॉयल्स की प्रतिबद्धता को और मजबूत करती है।

राजस्थान रॉयल्स की सामुदायिक पहलों का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका यह मैच टीम को उनकी खास ऑल-पिंक जर्सी में मैदान पर उतरते हुए देखेगा, जो महिलाओं के नेतृत्व वाले बदलाव के प्रति उनकी निरंतर निष्ठा का प्रतीक है। पिछले कुछ वर्षों में यह पहल क्रिकेट की पहुंच का उपयोग कर मैदान के बाहर भी वास्तविक और प्रभावशाली बदलाव लाने का एक मजबूत मंच बन चुकी है। पिंक प्रॉमिस फ्रेंचाइजी की वह मुहीम है, जो "औरत है तो भारत है" की सोच के साथ महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में काम करती है।

इस सीजन की पिंक प्रॉमिस जर्सी अपने साथ एक गहरी कहानी लेकर आई है। इसे 'Royals HunaRR Manch - Season 2 राजस्थान रॉयल्स पिंक प्रॉमिस जर्सी डिजाइन प्रतियोगिता' के माध्यम से तैयार किया गया है, जिसमें देशभर के 700 से अधिक डिजाइनर्स ने 8,500 से अधिक प्रविष्टियां भेजी थीं। यह जर्सी जमीनी स्तर पर बदलाव की भावना को दशार्ती है। महिलाओं के नेतृत्व वाले परिवर्तन की सोच पर आधारित इस डिजाइन में एक सूक्ष्म 'रिपल पैटर्न' शामिल है, जो यह दशार्ता है कि कैसे एक व्यक्ति से शुरू हुआ बदलाव परिवारों और समुदायों तक फैलता है। इस विजेता डिजाइन को नासिक की 19 वर्षीय समीक्षा रामेश्वर मुंडाडा ने तैयार किया है।

इस जर्सी में सोलर-प्रेरित डिजाइन एलिमेंट्स भी शामिल हैं, जो स्वच्छ और सतत ऊर्जा तक पहुंच का प्रतीक हैं। साथ ही, इसमें रॉयल राजस्थान फाउंडेशन द्वारा समर्थित महिलाओं के नाम भी शामिल किए गए हैं। ये सभी तत्व मिलकर "औरत है तो भारत है" की भावना को जीवंत करते हैं और इस जर्सी को केवल एक खेल किट नहीं, बल्कि सामाजिक प्रभाव की एक मिसाल बनाते हैं।

इस पहल पर बात करते हुए राजस्थान रॉयल्स के मुख्य परिचालन अधिकारी आलोक चित्रे ने कहा कि पिंक प्रॉमिस पिछले कुछ वर्षों में एक मजबूत अभियान बन चुका है, जहां क्रिकेट मैदान के बाहर भी सकारात्मक बदलाव का माध्यम बन रहा है।

उन्होंने बताया कि 2024 में इस पहल ने 260 घरों को रोशन करने में मदद की, जिसके बाद 2025 में यह संख्या 520 से अधिक घरों तक पहुंच गई। एक और सीजन में प्रवेश करते हुए टीम इस प्रभाव को और आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।

इस वर्ष भी राजस्थान रॉयल्स क्षेत्र में सोलर विद्युतीकरण के अपने प्रयास जारी रखेगा। मैच के दौरान लगाए गए हर छक्के पर 6 घरों को सोलर ऊर्जा से रोशन किया जाएगा, जिससे खेल के प्रदर्शन और सामाजिक सरोकार के बीच का संबंध और मजबूत होगा।

RNI No.: UPHIN/25/A1697 Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : ASHWANI KUMAR
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे के मद्देनजर सहारनपुर में रूट डायवर्ट, इन वैकल्पिक मार्गों का करें इस्तेमाल

(जीएनएस)।

सहारनपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को देवबंद में जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा में आने वाले कार्यकर्ता, पदाधिकारियों व आमजन मानस की भीड़ को देखते हुए सहारनपुर-मुजफ्फरनगर मार्ग पर यातायात परिवर्तित किया है।

एसपी ट्रैफिक शैलेंद्र श्रीवास्तव ने बताया वाहन चालकों से अनुरोध किया है कि वह जाम व अन्य दिक्कतों से बचने के लिए जारी किए गए रूटों पर ही यात्रा करेंगे। पुलिस ने एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस व आपातकालीन सेवाओं से जुड़े वाहनों को इस रूट पर चलने की छूट दी है।

इन रूटों का करें इस्तेमाल - सहारनपुर से देवबंद होकर मुजफ्फरनगर जाने वाले भारी वाहन कस्बा गागलहेड़ी, बडकला फ्लाईओवर, भगवानपुर मार्ग से होकर भेजे जाएंगे। वहीं हल्के वाहन सहारनपुर से देवबंद, बरला तिराहा, देवबंद-बरला मार्ग होते हुए छपार से मुजफ्फरनगर की ओर जाएंगे.

- मुजफ्फरनगर से देवबंद होते हुए सहारनपुर आने वाले हल्के वाहनों को रोहाना टोल, बर्फी, ग्राम चंदली, पंचकुड़ी मार्ग, पावटी कलां, चौहड़ा और काशीरामपुर होते हुए जामिया तिब्बिया कालेज के रास्ते सहारनपुर भेजा जाएगा।

बिजनौरः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नौ मई को अफजलगढ़ क्षेत्र के ग्राम आलमपुर गांवड़ी में कार्यक्रम प्रस्तावित है। कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री जनसभा को संबोधित करने के साथ-साथ विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित और विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे।

उधर जनसभा में भीड़ जुटाने में जहां भाजपा नेता जुटे हुए हैं। जनपद के प्रशासनिक अफसर भी ग्राम आलमपुर गांवड़ में 10 से 15 हजार लोगों की व्यवस्था करने में जुटे है। दो दिन पहले डीएम जसजीत कौर, एसपी अभिषेक झा और सीडीओ रणविजय सिंह ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के बाद जनसभा स्थल का निरीक्षण किया था।

इस दौरान डीएम ने संबंधित विभागों के अधिकारियो से विभिन योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों की सूची तलब की थी। सीडीओ रणविजय सिंह का कहना है कि अभी मुख्यमंत्री का कार्यक्रम नहीं मिला है। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार तैयारी की जा रही है।

लखनऊः बेटे की शादी के दिन पिता की मौत, चिता को आग देने के बाद दूल्हा बनकर गया बेटा; खुशियों की जगह मातम

(जीएनएस)।

लखनऊ। लखनऊ के निगोहां क्षेत्र में एक अजीब मामला सामने आया है। यहां एक पिता की मौत उसी दिन हुई जिस दिन उसके बेटे की शादी थी।

पूरा घर मंगल गीतों से गूंज रहा था। विवाह की रस्में धूमधाम से चल रही थीं। पूरे गांव में बरात निकलने की तैयारियां हो रही थीं कि तभी अचानक दूल्हे के पिता की तबीयत बिगड़ गई। अस्पताल ले गए पर उन्हें बचाया नहीं जा सका। शादी वाले घर में शहनाई की जगह क्रंदन गूंज उठा। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। पिता का अंतिम संस्कार कर दूल्हा देर शाम कुछ लोगों के साथ बरात लेकर दुखी मन से रायबरेली रवाना हुआ और वहां विवाह की रस्मअदायगी कर बुधवार को वापस आया। गांव में बरात आने की खुशियों की जगह मातमी सन्नाटा पसरा रहा।

मामला राजधानी के निगोहां गांव का है जहां 60 वर्षीय किसान भाईलाल कश्यप के सबसे छोटे बेटे रिंकू की मंगलवार को शादी थी। शाम को बरात रायबरेली के शिवगढ़ स्थित गांव बंकागढ़ जानी थी। बरात के लिए घर में रिश्तेदार जमा थे और गांव भर में तैयारियां चल रही थीं। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। सोमवार शाम हल्दी-मेहंदी की रस्म के दौरान भाईलाल की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। परिजनों ने निगोहां कस्बा स्थित एक निजी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया। मंगलवार सुबह उपचार के दौरान उनकी हालत ज्यादा गंभीर हो गई और इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। भाईलाल की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। उधर दूसरी ओर कन्या पक्ष तक जब खबर पहुंची तो वहां भी मातम छा गया।

भाईलाल के परिजन सकते में थे क्योंकि अंतिम संस्कार भी होना था और मंगलवार को ही बरात भी जानी थी। नाते-रिश्तेदारों की रजामंदी से तय हुआ कि भाईलाल के अंतिम संस्कार के बाद सादगी के साथ बरात रवाना होगी। मंगलवार शाम लगभग चार बजे गांव में ही भाईलाल का अंतिम संस्कार किया गया। इसके बाद भारी मन से रात लगभग आठ बजे सीमित बरातियों के साथ बरात रायबरेली के शिवगढ़ में स्थित बंकागढ़ निवासी रामनंद के यहां रवाना हुई। पहले से तय कार्यक्रम के चलते सादगी के साथ किसी तरह से विवाह की रस्में पूरी कराई गईं। बुधवार को रिंकू कश्यप अपनी नई नवेली दुल्हन रोहिनी को लेकर घर पहुंचे। इस दौरान घर-परिवार और गांव में उल्लास की जगह गम और सन्नाटा था। इस हृदयविदारक घटना की पूरे क्षेत्र में चर्चा रही। गांव वाले यही कह रहे थे कि भगवान ऐसा दिन किसी को भी न दिखाए।

लखनऊ में आईपलएल मैचों के दौरान सुरक्षा में इस्तेमाल होने वाले कैमरे बंद, गोमती नगर विस्तार में केस दर्ज

(जीएनएस)।

लखनऊ। इकाना स्टेडियम में गुरुवार को आईपीएल 2026 में गत विजेता रायल चैलेंजर्स बेंगलुरु और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच होने वाले मुकाबले से पहले ट्रैफिक मॉनिटरिंग और सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है। शहीद पथ पर लगे 40 कैमरे सीसीटीवी के उपकरण चोरी होने के कारण बेकार हैं। गोमती नगर विस्तार थाना में इस प्रकरण को लेकर केस दर्ज किया गया है।

लखनऊ में गोमती नगर विस्तार में सेफ सिटी परियोजना के तहत लगे सीसीटीवी कैमरों के उपकरण (स्विच, बैटरी, यूपीएस) चोरी हो गए हैं। जिसके कारण शहीद पथ पर करीब 40 कैमरे बंद हो गए हैं। इस चोरी से ट्रैफिक मॉनिटरिंग और सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित होने के बाद एफआईआर दर्ज कर ली गई है।

इन 40 कैमरों का उपयोग आईपीएल के दौरान ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए भी किया जाता था। गोमती नगर विस्तार और शहीद पथ क्षेत्र में स्मार्ट सिटी योजना के तहत लगाए गए कैमरों के स्विच, बैटरी और यूपीएस को चोर उठा ले गए। इसके कारण 40 कैमरे बंद हैं। इस चोरी के बाद महिला सुरक्षा और अपराध नियंत्रण पर असर पड़ेगा।

कैमरों का इस्तेमाल यातायात पुलिस द्वारा वाहनों की निगरानी और आईपीएल मैचों के दौरान ट्रैफिक मैनेजमेंट में किया जाता था। महिला सुरक्षा और अपराध नियंत्रण के लिए भी कैमरे अहम भूमिका निभा रहे थे। उपकरण गायब होने से फिलहाल कैमरे बंद पड़े हैं। पुलिस ने मामले इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आसपास लगे अन्य कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि चोरी करने वालों की पहचान की जा सके।

लखनऊ में जमीन न मिलने से अनूपगंज आरओबी की फंस गई सर्विस लेन, दो वर्ष से लटका पड़ा काम

आरओबी को रेलवे क्रासिंग संख्या 188 स्पेशल पर बनाया जा रहा

(जीएनएस)।

लखनऊ। राजधानी लखनऊ में पंद्रह लाख आबादी को राहत देने वाले रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) के कार्य की रफ्तार भले संतोषजनक हो, लेकिन सर्विस रोड न बन पाने के कारण यहां से गुजरने वाली एक बड़ी आबादी को परेशानी हो रही है।

यहां पर जहां पर सर्विस रोड का निर्माण होना था, वहां काश्तकारों ने अभी तक जमीन नहीं दी है। गोसाईगंज में बलियाखेड़ा के 103 काश्तकार और शिवलर के छह काश्तकार है। कुल 109 काश्तकारों में सिर्फ 75 काश्तकार ने जमीन देने पर सहमति दी है। बाकी काश्तकारों की जमीनों की रजिस्ट्री होनी बाकी है। इससे यहां सर्विस लेन नहीं बन पा रही है। एक बड़ी आबादी को पिछले डेढ़ वर्ष से परेशानी उठानी पड़ रही है।

यही नहीं शुरू में कार्यदायी संस्था ने आरओबी से जुड़े काम को भी धीमी गति से किया, लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम के एमडी के कार्यदायी संस्था को नोटिस देने के बाद काम की रफ्तार में कुछ सुधार हुआ। अधिकारियों के मुताबिक मार्च 2024 में शुरू हुए काम के हिसाब से रेल ओवर ब्रिज (आरओबी) का साठ प्रतिशत काम हो गया है। 718.678 मीटर लंबे आरओबी के निर्माण 14,044.78 लाख रुपये खर्च आ रहा है। निगम के अभियंताओं को आरओबी का काम मार्च 2028 तक पूरा करना है।

चार लेन के इस आरओबी को रेलवे क्रासिंग संख्या 188 स्पेशल पर बनाया जा रहा है। इस आरओबी के निर्माण से सुलतानपुर रोड से रायबरेली रोड व कानपुर रोड का सफर आसान हो जाएगा। इसके अलावा गोसाईगंज से सीधे मोहनलालगंज होते हुए प्रयागराज की कनेक्टिविटी मिल जाएगी एवं प्रयागराज आने वाले यातायात सुलतानपुर रोड पर जाने के लिए सीधे जुड़ा जाएंगा। यह मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसलिए दिल्ली, बरेली, सीतापुर, हरदोई आने जाने वाले भारी एवं हल्के वाहनों के लिए यातायात सुगम हो जाएगा।

उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम के अधिकारियों ने बताया कि 109 काश्तकारों में 75 काश्तकारों ने जमीन देने पर सहमति दे दी है। बचे हुए काश्तकारों की प्रकिया चल रही है। बता दें कि यहां तीन से चार परिसर भी रेलवे क्रासिंग से पहले आ रहे हैं, उन्हें तोड़ा जाएगा। इसमें एक परिसर शांति मिश्रा का है जो अपने सेतु निगम की गाइडलाइन का पालन करते हुए अपने चार मंजिला इमारत को निगम की गाइडलाइन के हिसाब से पीछे करवा रही हैं।

वहीं सेतु निगम के मुताबिक काश्तकारों को 2652.82 लाख रुपये मुआवजे के रूप में वितरित किया जाएगा। इसमें सर्किल रेट के हिसाब से जमीन की कीमत और जिनके परिसर आ रहे हैं, उसकी एक निर्धारित कीमत भी प्रशासन देगा। अगर वह अपना परिसर पीछे भी अपनी जमीन पर कर लेते हैं, तब भी यह धनराशि उन्हें दी जाएगी।

अब थमेगी प्रदेश में बारिश, फिर लौटेगी सताने वाली गर्मी, दस डिग्री चढ़ेगा पारा; जानें वैज्ञानिकों की कारण

(जीएनएस)।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मौसम साफ होने के साथ गर्मी फिर बढ़ने लगी है। बारिश कम होने से तापमान में लगातार वृद्धि होगी और उमस भी बढ़ेगी। अगले कुछ दिनों में तापमान 8 से 10 डिग्री तक बढ़ने की संभावना है, जिससे लोगों को तेज गर्मी का सामना करना पड़ेगा।

उत्तर प्रदेश में गर्मी दोबारा वापसी के लिए तैयार है। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी में विक्षोभ कमजोर पड़ा है और बुधवार को सिर्फ सिद्धार्थनगर आदि तराई इलाकों में बूंदाबांदी हुई। बृहस्पतिवार से प्रदेश में बारिश का दायरा सिमट जाएगा और तापमान में क्रमशः बढ़ोतरी दर्ज होगी। साथ ही हवा में नमी की मौजूदगी की वजह से उमस भरी गर्मी में इजाफा होगा। बृहस्पतिवार के लिए कहीं भी आंधी या बारिश की कोई चेतावनी नहीं है।

बुधवार को 38 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ बांदा प्रदेश में सर्वाधिक गर्म रहा। वहीं उरई में 37.2 डिग्री और झांसी में 36.9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ। 16 डिग्री के साथ नजीबाबादी में सबसे ठंडी रात रही। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र, लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि बृहस्पतिवार को तराई और दक्षिणी जिलों में हल्की बूंदाबांदी संभावित है। शुक्रवार से बारिश थमने के बाद अगले सात दिनों में तापमान में 8 से 10 डिग्री तक की बढ़त आएगी।

65 रुपये की किताब ₹700 में बेची, जांच में फंसे लखनऊ के दो नामी स्कूल, नोटिस का जवाब तक नहीं दे रहे अब

(जीएनएस)।

लखनऊ। जिला शुल्क नियामक समिति द्वारा जारी नोटिस के बावजूद के निजी विद्यालयों की मनमानी नहीं रुक रही है। समिति के नोटिस तक का जवाब नहीं दे रहे। जिला विद्यालय निरीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि शीलवती आइडल पब्लिक स्कूल और एलन हाउस पब्लिक स्कूल ने बुधवार को अपना जवाब दे दिया है।

विद्यालय प्रशासन अभिभावकों को एक निर्धारित दुकान से ही किताबें खरीदने का दबाव बना रहा था, जांच में आरोप भी सही पाया गया। एनसीइआरटी की 65 रुपये कीमत वाली किताबें निजी प्रकाशकों के माध्यम से 700 रुपये में दी जा रही थी। विद्यालयों से स्पष्टीकरण मांगा था।

विद्यालय के पक्ष और समिति द्वारा गठित जांच कमेटी के बीच विरोधाभास है। रिपोर्ट और विद्यालयों के पक्ष की जांच अगले दो दिनों में पूरी हो जाएगी। इसी सप्ताह कार्रवाई भी होगी। 25 विद्यालयों के विरुद्ध अभिभावकों ने शिकायत की थी। तीन विद्यालयों के विरुद्ध कार्रवाई की कई। अन्य का अभिभावकों की मौजूदगी में निस्तारण कर दिया गया।

लखनऊ या नोएडा, निवेश के लिए कौन सा शहर है 'हॉट' डेस्टिनेशन?

(जीएनएस)।

उत्तर प्रदेश का रियल एस्टेट बाजार इस समय अपने सबसे बेहतर युग से गुजर रहा है, जहां साल 2025 में कुल निवेश का आंकड़ा 68,000 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया, वहीं 2026 के 4 महीने में ही 25 हजार से ज्यादा निवेश किया जा चुका है. इस विकास यात्रा के केंद्र हैं यूपी के दो बड़े शहर नोएडा और लखनऊ हैं.

लंबे समय तक नोएडा सबसे ज्यादा डिमांड में रहा है. लेकिन यूपी रेरा के ताजा आंकड़े एक बड़े बदलाव की ओर इशारा करते हैं. साल 2025 में जहां नोएडा में 69 नए प्रोजेक्ट पंजीकृत हुए, वहीं लखनऊ 67 प्रोजेक्ट्स के साथ उसे कड़ी टक्कर दे रहा है. 2026 की शुरूआत में भी यह रुझान बरकरार है, जो यह दशार्ता है कि अब निवेशक और डेवलपर्स दोनों ही राजधानी लखनऊ को निवेश के एक 'पावर सेंटर' के रूप में देख रहे हैं.

वहीं नोएडा का सबसे बड़ा आकर्षण इसका विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर और जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसी मेगा परियोजनाएं हैं. दिल्ली-एनसीआर का हिस्सा होने के कारण यहां अंतरराष्ट्रीय मल्टीनेशनल कंपनियों और डेटा सेंटर्स की भरमार है. जो इसे रेंटल इनकम के लिए सबसे सुरक्षित विकल्प बनाता है.

हालांकि, नोएडा में प्रॉपर्टी की कीमतों में अब ठहराव देखा जा सकता है, जिससे यहां भविष्य में कीमतों में बहुत अधिक उछाल की गुंजाइश सीमित है. यहां का जीवन काफी तेज है, लेकिन प्रदूषण और कंक्रीट के बढ़ते जंगल जीवन की गुणवत्ता के सामने बड़ी चुनौती पेश करते हैं.

इसके विपरीत, लखनऊ इस समय 'कैपिटल एप्रिसिएशन' यानी संपत्ति के दामों में बढ़ोतरी के मामले में नोएडा से आगे निकलता दिख रहा है. अमर शहीद पथ, सुल्तानपुर रोड और आउटर रिंग रोड जैसे इलाकों में बुनियादी ढांचे के विस्तार ने निवेशकों को आकर्षित किया है. लखनऊ में जमीन और फ्लैट की कीमतें नोएडा के मुकाबले अभी भी कम हैं, जिससे मध्यम वर्गीय निवेशकों के लिए यहां मुनाफे की संभावना अधिक है. साथ ही, उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी होने और बेहतर वायु गुणवत्ता के कारण लोग यहां रहने को भी प्राथमिकता दे रहे हैं. यूपी रेरा की हालिया रिपोर्ट बताती है कि लखनऊ अब सिर्फ रहने के लिए नहीं, बल्कि व्यावसायिक लाभ के लिए भी एक बड़ा ग्रोथ हब बन चुका है.

यह भी पढ़ेंः क्या काले धन को खपाने का जरिया है रियल एस्टेट, रेरा पर क्यों नहीं है लोगों को भरोसा!

2026 में निवेश का फैसला आपके लक्ष्यों पर निर्भर करता है, अगर आप तुरंत और सुरक्षित रेंटल इनकम चाहते हैं और आपका बजट अधिक है, तो नोएडा आपके लिए बेहतर विकल्प है, लेकिन अगर आप लंबी अवधि में अपनी संपत्ति की कीमत को दोगुना या तिगुना होते देखना चाहते हैं और एक किफायती बजट में निवेश की तलाश में हैं, तो लखनऊ निश्चित रूप से एक 'गोल्ड माइन' साबित होगा. यूपी रेरा द्वारा फ्लैट ट्रांसफर फीस में की गई हालिया कटौती और नियमों में पारदर्शिता ने दोनों ही शहरों में घर खरीदारों के विश्वास को और मजबूत किया है.

स्मार्ट मीटर प्रीपेड होगा या पोस्टपेड? बिलिंग पर संशय बरकरार, लखनऊ के दिशा-निर्देशों सम्बंधी आदेश का इंतजार

(जीएनएस)।

कानपुर। सरकार ने प्रीपेड स्मार्ट मीटर पर रोक भले ही लग दी हो, लेकिन केस्को में अभी इसकी तस्वीर साफ नहीं है। केस्को के अधिकारी दिशा-निर्देशों (एसओपी) के जारी होने का इंतजार कर रहे हैं। वैसे कुछ अधिकारी बता रहे हैं कि मई महीने का जो एक जून बिल आएगा, वह पोस्टपेड आधारित होगा। नए कनेक्शन में उपभोक्ता को पोस्टपेड स्मार्ट मीटर मिलेगा या फिर प्रीपेड, इस बारे में भी अधिशासी अभियंता-मीटर कुछ स्पष्ट नहीं बता पा रहे हैं।

महानगर में केस्को के 7.70 लाख उपभोक्ता हैं। इनमें 1.41 लाख कनेक्शनों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर से बिलिंग हो रही है। पिछले दिनों काफी विरोध को देखते हुए सरकार ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर पर रोक लगा दी। इसके बाद उपभोक्ता यह जानने के लिए परेशान हैं कि अब उन्हें बिल का भुगतान प्रीपेड या पोस्टपेड बिलिंग के आधार पर करना होगा।

इस बारे में अधिशासी अभियंता-स्मार्ट मीटर सुनील आर्यन का कहना है कि उनका काम उपभोक्ता को कनेक्शन मिलने के बाद मीटर इंस्टालेशन का है। वह आनलाइन मीटर नंबर दर्ज कर मुख्यालय शक्ति भवन को फारवर्ड करते हैं। फिर वहीं से स्मार्ट मीटर की बिलिंग प्रीपेड रहेगी या पोस्टपेड, निर्धारित होता है।

उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं को बिल पोस्टपेड या प्रीपेड के हिसाब में अदा करने होंगे, यह सब शक्ति भवन लखनऊ से तय होगा। दूसरी तरफ, न्यू सर्विस कनेक्शन सेल के अधिशासी अभियंता दीपक शुक्ला का कहना है कि कनेक्शन देकर मीटर लगाना उनका काम है, लेकिन मीटर पोस्टपेड होगा या प्रीपेड, यह तय करना स्मार्ट मीटर के अधिशासी अभियंता का है।

नए कनेक्शन के साथ स्मार्ट मीटर लगाने में भी दरें हर बार बदल रही हैं। उपभोक्ताओं ने बताया कि वर्ष 2018 से 2022 तक शुरूआती दौर में एक किलोवाट का कनेक्शन स्मार्ट मीटर समेत 1,799 रुपये का था और दो किलोवाट के कनेक्शन पर 2,099 रुपय लगते थे। यह दरें बढ़कर वर्तमान में एक किलोवाट के कनेक्शन पर 5,300 और दो किलोवाट पर 5,600 रुपये से भी अधिक खर्च आ रहा है।

बढ़ी दरों में दो किलोवाट के कनेक्शन के लिए स्मार्ट मीटर की लागत 2800, लाइन चार्ज 1400 रुपये के साथ ही 600 रिचार्ज दिया जा रहा है। जबकि, एक किलोवाट में रिचार्ज की कीमत आधी अर्थात 300 रुपये लिए जा रहे हैं। कमर्शियल के दो किलोवाट के कनेक्शन पर 7,200 रुपये खर्च आ रहा है। इसमें 2800 रुपये का स्मार्ट मीटर के साथ ही लाइन चार्ज और 2000 रुपये रिचार्ज के लिए जा रहे हैं। लाइन चार्ज स्थिति के अनुसार घटता-बढ़ता रहता है।

स्मार्ट प्रीपेड मीटर पर रोक लगा दी गई है, लेकिन अभी इस संबंध में एसओपी जारी नहीं हुई है। स्मार्ट मीटर से बिलिंग की जो भी प्रक्रिया निश्चित की जएगी, उसका अनुपालन किया जाएगा। रही बात नए कनेक्शन के चार्ज की तो यूपी-आरसी की तरफ स्वीकृत दरों के आधार पर ही प्राक्लन आवेदनकर्ता को उपलब्ध कराए जाते हैं।

क्या टूटेगी पुरानी दूरियां? भाजपा गठबंधन पर अकाली दल का बड़ा संकेत

(जीएनएस)।

पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल गमार्ता जा रहा है। इसी बीच शिरोमणि अकाली दल (पुनर-सुरजीत) की नेता बीबी जागीर कौर के एक बयान ने राज्य की सियासत में नई चर्चा छेड़ दी है।

उन्होंने साफ कहा है कि यदि पंथिक मुद्दों का सम्मानजनक समाधान होता है, तो उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन के लिए तैयार है।

बीबी जागीर कौर ने अपने बयान में स्पष्ट किया कि उनकी प्राथमिकता सत्ता नहीं, बल्कि सिख समुदाय से जुड़े पंथिक मुद्दे हैं। उन्होंने कहा कि अगर इन मुद्दों पर सकारात्मक रुख अपनाया जाता है और समुदाय की भावनाओं का सम्मान होता है, तभी किसी भी तरह के राजनीतिक गठबंधन पर विचार किया जा सकता है। उनका यह बयान इस ओर इशारा करता है कि आने वाले चुनावों में मुद्दा-आधारित गठबंधन देखने को मिल सकता है।

बीबी जागीर कौर ने स्पष्ट किया कि भाजपा के साथ किसी भी प्रकार का राजनीतिक समझौता केवल पंजाब और सिखों के हितों पर ही आधारित होगा। उन्होंने कहा- "हम भाजपा के साथ गठबंधन के प्रति पूरी तरह बंद नहीं हैं, लेकिन हमारी पहली शर्त पंथिक मुद्दों का समाधान है। इसमें बंदी सिखों की रिहाई, धार्मिक मामलों में सरकारी हस्तक्षेप का अंत और एसजीपीसी के चुनावों का समय पर आयोजन जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं।"

गौरतलब है कि भाजपा और शिरोमणी अकाली दल का गठबंधन 1996 से चला आ रहा था, जो 2021 में किसान आंदोलनों के दौरान टूट गया था। 2022 के विधानसभा चुनाव दोनों ने अलग-अलग लड़े थे, जहां अकाली दल को केवल 3 और भाजपा को 2 सीटें मिली थीं। इसके बाद से दोनों दल अलग-अलग चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन बदलते राजनीतिक हालात अब एक बार फिर संभावित नजदीकियों की ओर इशारा कर रहे हैं। अब बीबी जागीर कौर के इस रुख से संकेत मिल रहे हैं कि पंजाब में एक बार फिर 'पुराने साथियों' का मेल हो सकता है, लेकिन इस बार चेहरे और शर्तें बदली हुई होंगी।

पंजाब की राजनीति में फिलहाल आम आदमी पार्टी (अअढ), कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल और भाजपा जैसे कई खिलाड़ी सक्रिय हैं। ऐसे में किसी एक पार्टी के लिए स्पष्ट बहुमत हासिल करना आसान नहीं माना जा रहा। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक, इसी वजह से छोटे दलों और क्षेत्रीय नेताओं की भूमिका इस बार निर्णायक हो सकती है।

बिहार कैबिनेट विस्तार में पीएम मोदी भी होंगे शामिल, पटना में रोड शो सहित जानें पूरा शेड्यूल

पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में सम्राट चौधरी मंत्रिमंडल का गुरुवार को विस्तार होगा. इस आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी कार्यक्रम में पहुंचेंगे.

(जीएनएस)।

पटना, बिहार कैबिनेट विस्तार पटना के गांधी मैदान में दोपहर 12.10 पर होगा. इसके लिए तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है. पीएम नरेंद्र मोदी समारोह में शामिल होने के लिए सुबह 10.30 बजे पटना एयरपोर्ट पहुंचेंगे और रोड शो भी करेंगे.केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन समेत कई नेता पटना आएंगे.

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल का विस्तार गुरुवार को होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में लगभग पूरी हो चुकी हैं. बिहार कैबिनेट विस्‍तार का कार्यक्रम

दोपहर 12:10 बजे आयोजित होगा और इसे लेकर राज्य में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गुरुवार को सुबह पटना पहुंचेंगे. समारोह को भव्य बनाने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं और पूरे शहर में जगह-जगह स्वागत पोस्टर लगाए गए हैं, जिनमें 'विकसित भारत, विकसित बिहार' का संदेश प्रमुखता से दिख रहा है.

पटना के गांधी मैदान में गुरुवार को दोपहर 12.10 पर कैबिनेट के विस्‍तार का कार्यक्रम का आयोजन होगा. इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह साढ़े 10 बजे पटना एयरपोर्ट पहुंचेगे. इसके बाद पीएम मोदी का पटना एयरपोर्ट से गांधी मैदान तक रोड शो होगा.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी सुबह करीब 8:30 बजे ही पटना पहुंच जाएंगे. इनके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा और कई अन्य केंद्रीय नेता भी समारोह में भाग लेंगे.

एनडीए के प्रमुख दलों के नेता भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे, जिनमें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी शामिल हैं. इसके साथ ही बिहार से जुड़े एनडीए के सभी सांसद और केंद्र सरकार में राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले मंत्री भी शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगे.

मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर राजनीतिक दृष्टि से इसे बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जहां एक ओर नई टीम का गठन होगा, वहीं दूसरी ओर एनडीए अपनी एकजुटता और ताकत का प्रदर्शन भी करेगा.

करोड़ों का एक्सप्रेसवे और उल्टा ढाल, यूपी में एनएएआई की बड़ी चूक आई सामने, एजेंसी कर रही सुधार कार्य

लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे की एलिवेटेड रोड पर जलभराव की समस्या है क्योंकि बरसाती पानी की निकासी के लिए लगाए गए पाइपों की ढाल नालों की ओर सही नहीं है।

(जीएनएस)।

बंथरा (लखनऊ)। लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे एलिवेटेड रोड पर बरसात का पानी निकलने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) ने सड़क के दोनों तरफ नाले बनाए हैं। इन नालों में बरसात का पानी जा नहीं पा रहा है। क्योंकि कार्यदायी संस्था ने एलीवेटेड रोड से जो बरसाती पानी की निकासी के लिए पाइप, पिलर के सहारे उतारे हैं उनकी ढाल नालों की तरफ सही नहीं है।

इसके कारण बरसात का पानी

सड़क पर फैल रहा है। पिछले चंद दिनों में हुई बरसात में यह समस्या यहां देखी गई। कई स्थानों पर नाला निर्माण से जुड़ा कार्य अधूरा पड़ा है।

बरसात में पानी की ढाल नाले की तरफ न होने से जलभराव हो रहा है। यह समस्या बंथरा कस्बे से लेकर थाने तक कई स्थानों पर है। यह स्थिति तब है जब एक्सप्रेसवे का निर्माण करने वाली एजेंसी अभी काम कर रही है। स्थानीय लोगों का तर्क है कि अभी बरसात का पूरा सीजन बाकी है।

अगर यही स्थिति रही तो यहां जलभराव हो जाएगा और एक्सप्रेसवे की सड़क जलभराव के कारण जल्द खराब हो जाएगी। जलभराव के कारण एक्सप्रेसवे के किनारे रहने वाले लोग और उनके प्रतिष्ठान प्रभावित होंगे। उधर एलिवेटेड रोड निर्माण के दौरान कंक्रीट व कूड़ा भी इन पाइप में जम गया है।

इससे एलिवेटेड रोड पर भी बरसात के जलभराव रहता है और पानी काफी धीमी गति से कई स्थानों पर निकल पा रहा है। कार्यदायी संस्था के प्रशासनिक अधिकारी अंकित ने बताया कि जो नाले से जुड़ा कार्य हो रहा है। जहां ढाल ठीक नहीं है उसे भी ठीक कराया जा रहा है।

लखनऊ एटीएस ने बाराबंकी से 2 संदिग्ध आतंकियों को किया गिरफ्तार, पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी से मिला संपर्क

(जीएनएस)।

लखनऊ एटीएस ने 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है. एटीएस द्वारा बाराबंकी के दानियाल और कुशीनगर के कृष्णा दबोचा गया है. इन दोनो के पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी से संपर्क के सबूत मिले हैं. एटीएस ने वीडियो कॉल, वॉइस नोट और ग्रुप कॉल रिकॉर्ड बरामद किए हैं. दोनों के ऊपर संवेदनशील

स्थानों की रेकी कर फुटेज भेजने के आरोप हैं.

आरोपियों ने पुलिस स्टेशन और प्रतिष्ठानों की जानकारी भी साझा की है. पैसे और हथियार मांगने के सबूत भी मिले हैं. एक आरोपी को वदीर्धारी पर हमला करने का टास्क मिला था. सोशल मीडिया से स्लीपर सेल तैयार करने की साजिश रची गई. आरोपियों से पूछताछ जारी है. साथ ही एटीएस द्वारा अन्य साथियों की तलाश में छापेमारी की जा रही है.

सम्राट कैबिनेट का बड़ा धमाका, एआई मिशन को मंजूरी, 400 इलेक्ट्रिक बसों से चकाचक होंगे शहर

(जीएनएस)।

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास और तकनीकी ढांचे को आधुनिक बनाने के लिए कई क्रांतिकारी निर्णयों पर मुहर लगाई गई। इस बैठक में कुल 20 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जो सीधे तौर पर आम जनता की सहूलियत और प्रशासनिक दक्षता से जुड़े हैं।

सरकार का मुख्य विजन 'डिजिटल बिहार' की संकल्पना को साकार करना है, जिसमें तकनीक के माध्यम से पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। इन फैसलों में सबसे खास 'बिहार एआई मिशन' की शुरूआत और शहरी परिवहन को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए सैकड़ों इलेक्ट्रिक बसों की खरीद है। इसके अलावा, धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को सम्मान देते हुए सीतामढ़ी मेडिकल कॉलेज के नामकरण में भी बदलाव किया गया है।

राज्य में गवर्नेंस को स्मार्ट बनाने के लिए सरकार ने 'बिहार एआई

मिशन' को हरी झंडी दे दी है। इस पहल के तहत सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। इस तकनीक का लाभ मुख्य रूप से कृषि, स्वास्थ्य सेवा, वित्त और प्रशासनिक कार्यों में लिया जाएगा। एआई के समावेश से अब सरकारी निर्णय डेटा और सटीक विश्लेषण पर आधारित होंगे, जिससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और फाइलों का निपटारा तेजी से होगा।

स्थानीय जनभावनाओं और सांस्कृतिक गौरव को प्राथमिकता देते हुए कैबिनेट ने सीतामढ़ी में निमार्णाधीन मेडिकल कॉलेज के नाम बदलने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। अब इसे 'मां सीता चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल' के नाम से जाना जाएगा। चूंकि सीतामढ़ी को मां सीता की पावन प्राकट्य स्थली माना जाता है, इसलिए यह निर्णय क्षेत्र की धार्मिक पहचान को वैश्विक पटल पर मजबूती देगा।

प्रदूषण मुक्त सफर, चलेंगी 400 इलेक्ट्रिक बसें

बिहार के प्रमुख शहरों में सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने के लिए 400 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाने का निर्णय लिया गया है। इस योजना का विवरण निम्नलिखित है:

पटना: 150 बसें।

मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, दरभंगा और पूर्णिया: प्रत्येक शहर को 50-50 बसें मिलेंगी।

बजट: इस पूरी योजना पर 517 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया जाएगा।

अवधि: यह प्रोजेक्ट अगले 12 वर्षों तक प्रभावी रहेगा, जिससे न केवल यातायात सुलभ होगा बल्कि शहरों में कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा।

जेडीयू की फाइनल लिस्ट आ गई सामने, क्या निशांत कुमार भी बनेंगे सम्राट कैबिनेट में मंत्री?

(जीएनएस)।

बिहार की सियासत के लिए बुधवार का दिन बेहद ऐतिहासिक और निर्णायक होने जा रहा है। 7 मई को राजधानी पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान एक बड़े राजनीतिक बदलाव का साक्षी बनेगा, जहां नीतीश सरकार के नए मंत्रिमंडल का भव्य विस्तार कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

इस समारोह को लेकर राज्य का राजनीतिक पारा सातवें आसमान पर है और सत्ता के गलियारों में संभावित मंत्रियों के नामों को लेकर अटकलों का दौर तेज हो गया है। माना जा रहा है कि इस बार एनडीए गठबंधन ने 'मिशन 2025' को ध्यान में रखते हुए सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने की पूरी कोशिश की है। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी शामिल होने की संभावना है, जिससे इस कार्यक्रम का राजनीतिक कद और भी बढ़ गया है।

जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) अपने कोटे से अनुभव और युवा ऊर्जा के मेल पर भरोसा जताती दिख रही है। चर्चा है कि बिजेंद्र यादव और विजय चौधरी जैसे कद्दावर नेताओं की जगह बरकरार रहेगी। इनके अलावा श्रवण कुमार, अशोक चौधरी जैसे नामों पर मुहर लग सकती है। जेडीयू की संभावित सूची में सुनील कुमार, शीला मंडल भी शामिल हैं। हालांकि, सबसे अधिक चर्चा निशांत कुमार को लेकर हो रही है, जिनका नाम सियासी हलकों में कौतूहल का विषय बना हुआ है।

अंत्योदय से औद्योगिक क्रांति तक: योगी आदित्यनाथ ने कैसे बदली उत्तर प्रदेश की नियति

(जीएनएस)।

नई दिल्ली, योगी सरकार की समावेशी नीति 'अंत्योदय' को साकार कर रही है। एक्सप्रेसवे, डिफेंस कॉरिडोर और औद्योगिक हब्स के माध्यम से यूपी अब 'बीमारू' राज्य से देश का 'ग्रोथ इंजन' बन चुका है। डउद्धढ और बेहतर सुशासन ने पलायन रोका है और करोड़ों युवाओं व कारीगरों को आत्मनिर्भर बनाकर राज्य को नई आर्थिक पहचान दी है।

अंत्योदय की अवधारणा जब नीति की भाषा बनती है, जब योजनाओं की स्याही में उतरती है और जब जमीन पर साकार होती है तो इतिहास उसे केवल शासन नहीं, एक सभ्यतागत घटना कहता है। उत्तर प्रदेश आज ऐसी ही एक सभ्यतागत घटना का साक्षी है और पं. दीनदयाल उपाध्याय की उस अवधारणा को साकार कर रहा है, जिसमें वह विकास की परिभाषा अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के जीवन में आए उजाले को मानते थे। ऐसा इसलिए है कि अब नेतृत्व में संकल्प दिखाई देता है, नीति में स्पष्टता है और सुशासन की नींव पर समावेशी विकास की इमारत खड़ी दिखाई देती है।

आज उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में जो एक्सप्रेसवे व कॉरिडोर बन रहे हैं, जो क्लस्टर आकार ले रहे हैं, जो इंडस्ट्रियल पार्क व हब जीवंत हो रहे हैं, वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की समावेशी विकास नीति का मूर्त रूप हैं। वे उत्तर प्रदेश में दशकों से चली आ रही आर्थिक असमानता को मिटाने के उपकरण हैं। यह प्रदेश में कंक्रीट से संवारे जा रहे समावेशी विकास की जीवंत तस्वीर भी है।

उत्तर प्रदेश कभी अपनी विशालता के बोझ तले दबा था। इतनी बड़ी आबादी, इतना विस्तृत भूगोल, इतनी गहरी विषमताएं और इन सबके बीच एक ऐसी व्यवस्था जो थकी हुई थी, जो अपने ही नागरिकों को रोक नहीं पाती थी, जो पलायन को नियति मान चुकी थी। बुंदेलखंड की फटी धरती, पूर्वांचल की सूनी गलियां और पश्चिम की दबी हुई औद्योगिक क्षमता, यह उत्तर प्रदेश की वह तस्वीर थी जो दशकों से बदलने का नाम नहीं ले रही थी। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जब 2017 में कमान संभाली, तो उत्तर प्रदेश की पहचान बीमारू राज्य के रूप में थी। तब किसी ने शायद सोचा भी न था कि एक दिन यही प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दौड़ में सबसे तेज धावक होगा, भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बनेगा।

राज्य में विकसित हुए विभिन्न एक्सप्रेसवे, कॉरिडोर्स, क्लस्टर्स, विशेष पार्क व हब भविष्य की अर्थव्यवस्था की बड़ी ताकत साबित होंगे। आगरा से लखनऊ, कानपुर, झांसी और चित्रकूट को जोड़नेवाला डिफेंस कॉरिडोर केवल एक औद्योगिक परियोजना नहीं है, यह एक सामाजिक संकल्प है। इस परियोजना के अंतर्गत अब तक लगभग दो सौ एमओयू पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। हस्ताक्षरित एमओयू के सापेक्ष हजारों करोड़ के निवेश तथा पचास हजार से ज्यादा लोगों के प्रत्यक्ष रोजगार का अनुमान है।

अप्रत्यक्ष रूप में कितनों को रोजगार मिलेगा, इसकी कल्पना सहज ही की जा सकती है। लेकिन, इससे बड़ी बात यह है कि बुंदेलखंड जो दशकों से सूखे, पलायन और निराशा की कहानी था, अब एक नई पहचान बना रहा है। झांसी की वह भूमि जहाँ कभी रानी लक्ष्मीबाई ने वीरता की इबारत लिखी थी, आज फिर से एक नई शक्ति का केंद्र बन रही है। जब किसी क्षेत्र का युवा पलायन बंद करता है और जड़ें पकड़ता है, तो यह केवल आर्थिक घटना नहीं है, यह सामाजिक पुनर्जन्म है।

आत्मनिर्भरता की नई परिभाषा

भारत की आत्मा गांवों में बसती है और योगी सरकार ने इस आत्मा को आर्थिक शक्ति देने का बीड़ा उठाया है। एक जनपद-एक उत्पाद जैसी योजना एक करोड़ से अधिक कारीगरों को प्रत्यक्ष लाभ देती है। जब वाराणसी का कोई बुनकर अपनी साड़ी सीधे ई-कॉमर्स प्लेटफार्म पर बेचने लगता है, तो वह केवल एक व्यापारी नहीं बनता, वह आत्मनिर्भरता की नई परिभाषा गढ़ता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे क्षमता विस्तार के नए साधन हैं। जब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक क्लस्टर बनते हैं, तो आजमगढ़ और मऊ का युवक सूरत या मुंबई जाने की मजबूरी से मुक्त होता है।

गंगा एक्सप्रेसवे पर जब इंडस्ट्रियल नोड्स विकसित होते हैं, तो मेरठ से प्रयागराज तक का पूरा भूगोल बदल जाता है। ग्रेटर नोएडा में आईआईटीजीएनएल, बरेली में मेगा फूड पार्क, उन्नाव में ट्रांसगंगा सिटी, गोरखपुर में प्लास्टिक पार्क, गोरखपुर में गारमेंट पार्क तथा अनेक फ्लेटेड फैक्ट्री परिसर, यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ ही फिल्म सिटी, टॉय पार्क, अपैरल पार्क, हैंडीक्राफ्ट पार्क, लॉजिस्टिक हब व ऐसी ही अन्य योजनाएं आर्थिक ताकत की रीढ़ साबित होंगी।

नोएडा और ग्रेटर नोएडा में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर आज देश के सबसे बड़े मोबाइल उत्पादन केंद्रों में से एक है। सैमसंग, ओप्पो, वीवो जैसी विश्वस्तरीय कंपनियों की उपस्थिति ने यहां एक पूरा पारिस्थितिकी तंत्र खड़ा किया है। लेकिन इस इकोसिस्टम की असली कहानी उन हजारों छोटे उद्यमियों की है जो इन बड़ी कंपनियों के लिए कंपोनेंट बना रहे हैं। उन युवा इंजीनियरों की है जो अपने शहर में ही अपनी क्षमता को मूर्त रूप दे रहे हैं। डॉ. भीमराव अंबेडकर ने कहा था, 'राजनीतिक लोकतंत्र तब तक टिक नहीं सकता जब तक उसकी नींव में सामाजिक लोकतंत्र न हो।' योगी सरकार की औद्योगिक नीति इसी सिद्धांत पर आधारित है।

ग्रेटर नोएडा में विकसित हो रहा डेटा सेंटर पार्क इसी बात की मिसाल है। यह पार्क न केवल डिजिटल अर्थव्यवस्था की नींव रखेगा, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए उच्च-कौशल रोजगार के नए द्वार खोलेगा। वस्त्र उद्योग पर विशेष ध्यान देना भी इस संदर्भ में अत्यंत प्रासंगिक है। प्रदेश में लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, मुरादाबाद, बरेली और आगरा में टेक्सटाइल पार्क और हैंडलूम क्लस्टर विकसित हो रहे हैं। भारत के कुल हस्तशिल्प निर्यात में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 40 प्रतिशत से अधिक है। यह न केवल विदेशी मुद्रा अर्जन का माध्यम है, बल्कि उन लाखों हाथों की गरिमा का प्रश्न भी है जो पीढ़ियों से इस कला को जीवित रखे हुए हैं।

समाधान का मॉडल बनता राज्य

सुशासन केवल प्रशासनिक उपलब्धि नहीं, नैतिक और सामाजिक विजय है। इन्वेस्ट यूपी की स्थापना और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में प्रदेश की बेहतर रैंकिंग ने निवेश के वातावरण को जो नई ऊंचाई दी है, उसका सामाजिक अनुवाद यह है कि भ्रष्टाचार घटा है, पारदर्शिता बढ़ी है, और सरकार पर नागरिकों का विश्वास मजबूत हुआ है। लॉजिस्टिक्स पार्क और मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट हब का जाल बिछाते हुए योगी सरकार ने एक ऐसी कनेक्टिविटी दी है जो प्रदेश के हर कोने को एक साथ धड़कने की ताकत देती है। दादरी में विकसित हो रहा मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स हब एशिया के सबसे बड़े लॉजिस्टिक्स केंद्रों में से एक बनने की राह पर है। जब माल तेजी से पहुँचता है, जब किसान की उपज समय पर बाजार तक जाती है, जब निर्यातक की समयसीमा पूरी होती है तो इस पूरे चक्र में लाभान्वित होने वाला अंतिम व्यक्ति भी वही है, जो इस श्रृंखला की नींव है।

उत्तर प्रदेश में हो रहा यह औद्योगिक और अवसंरचनात्मक परिवर्तन उस समाज की कहानी है जो सदियों की उपेक्षा के बाद अपनी नियति खुद लिख रहा है। जो प्रदेश कभी समस्याओं का प्रतीक था, आज समाधानों का मॉडल बन रहा है। इतिहास जब इस कालखंड को देखेगा, तो वह इसे महज आर्थिक उछाल नहीं कहेगा, वह इसे एक सभ्यतागत पुनर्जागरण कहेगा। हालांकि, इस स्वर्णिम तस्वीर के बीच कुछ कठिन सच्चाइयां भी हैं जिन्हें नजरअंदाज करना उचित नहीं होगा। पर्यावरणीय स्थिरता के सवाल, विशेषकर जल संसाधनों पर बढ़ते दबाव और औद्योगिक प्रदूषण के खतरे, भविष्य की नीति-निर्माण के लिए गंभीर विचार मांगते हैं। लेकिन जो समाज अपनी कमजोरियों को पहचानकर उनसे लड़ता है, वही स्थायी परिवर्तन की नींव रख सकता है।

कौन है कांग्रेस विधायक डॉ. थारहाई कुथबट 'मछुआरा बेटी'? टीवीके प्रत्याशी को चटाई धूल, अब विजय बनाएंगे मंत्री!

(जीएनएस)।

तमिलनाडु की राजनीति में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। थलापति जोसेफ विजय चंद्रशेखर की तमिलगा वेट्टी कझगम (टीवीके) ने 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन बहुमत से 10 सीटें कम रह गईं। अब टीवीके-कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनने जा रही है।

कांग्रेस को 2 कैबिनेट बर्थ मिलने की पूरी संभावना है और सूत्रों के मुताबिक कुलाचल (कोलाचेल) सीट से जीतने वाली कांग्रेस विधायक डॉ. थारहाई कुथबर्ट का नाम मंत्री पद के लिए सबसे तेजी से चर्चा में है। यह नाम सिर्फ एक विधायक का नहीं, बल्कि 60 साल पुरानी राजनीतिक खाई को पाटने और सामाजिक न्याय की नई मिसाल बनने वाला है। आइए विस्तार से जानते हैं आखिर कौन है ये कांग्रेस की 'मछुआरा बेटी'?

2026 के विधानसभा चुनाव में कोलाचेल सीट पर कड़ी टक्कर थी। टीवीके के उम्मीदवार प्रेम एलेक्स लॉरेंस को 63,374 वोट मिले, लेकिन डॉ. थारहाई कुथबर्ट ने 66,207 वोट हासिल कर 2,833 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। यह जीत इसलिए खास है क्योंकि टीवीके की लहर पूरे राज्य में थी, लेकिन कन्याकुमारी जिले के इस मछुआरा बहुल क्षेत्र में कांग्रेस ने अपनी पकड़ बनाए रखी।

थारहाई ने पहले 2024 में विलवन्कोड उपचुनाव में इखढ उम्मीदवार को करीब 40,000 वोटों से हराया था। अब 2026 में कोलाचेल से दोबारा मैदान में उतरकर उन्होंने साबित किया कि कांग्रेस का स्थानीय आधार अभी भी मजबूत है।

मछुआरा समुदाय की बेटी, कामराज युग की विरासत

डॉ. थारहाई कुथबर्ट (उम्र 51 वर्ष) कन्याकुमारी जिले के मछुआरा (रोमन कैथोलिक फिशर) समुदाय से ताल्लुक रखती हैं। उनका राजनीतिक सफर कांग्रेस संगठन से शुरू हुआ। उन्होंने कांग्रेस महिला विंग, जिला

स्तर के पद और कन्याकुमारी वेस्ट जिला अध्यक्ष का दायित्व संभाला। अकऊउ सदस्य के रूप में भी सक्रिय रहीं।

सबसे दिलचस्प बात ये है कि वे उसी कोलाचेल क्षेत्र से हैं जहां 1957-62 के कामराज मंत्रिमंडल में लुरधम्मल साइमन तमिलनाडु की पहली महिला मंत्री बनी थीं। 1962 के बाद कांग्रेस ने यहां मछुआरा समुदाय से कोई महिला उम्मीदवार नहीं उतारा था। 64 साल बाद थारहाई कुथबर्ट ने उस खाली जगह को भरा।

माइनेटा के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति करीब ₹4.5 करोड़ है, जबकि देनदारियां ₹41 लाख के आसपास। कोई आपराधिक मामले नहीं। उन्होंने डॉक्टरेट की पढ़ाई पूरी की है। स्थानीय मुद्दों- सड़क, पानी, मछुआरों की आजीविका पर उनका फोकस हमेशा रहा।

गठबंधन की बातचीत के अंतिम चरण में थारहाई ने इंस्टाग्राम पर थलापति विजय से मुलाकात की तस्वीर पोस्ट की। साथ में तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष सेल्वप्पेरुंदगई, अकऊउ प्रभारी कृष्ण चोडनकर और सचिव निवेदिथ अल्वा भी थे। पोस्ट में उन्होंने लिखा कि गठबंधन समझौते पर चर्चा हुई। यह तस्वीर कांग्रेस-टीवीके गठबंधन की मजबूती का प्रतीक बन गई।

60 साल बाद कांग्रेस का मंत्रिमंडल में वापसी - ऐतिहासिक मोड़

1967 में द्रविड़ दलों के उदय के बाद कांग्रेस तमिलनाडु में सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा नहीं बन पाई। पेरुंथलाइवर कामराज के युग के बाद यह पहला मौका है जब कांग्रेस मंत्रिमंडल में बैठेगी। अगर थारहाई मंत्री बनीं तो यह दो मायनों में मील का पत्थर होगा:

1. महिला सशक्तिकरण: मछुआरा समुदाय की बेटी को मंत्री पद।

2. सामाजिक न्याय: दक्षिण तमिलनाडु के तटीय इलाकों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को आवाज मिलेगी।

कांग्रेस नेतृत्व ने साफ कहा कि जनता ने धर्मनिरपेक्ष सरकार का जनादेश दिया है। हम टीवीके को सशर्त समर्थन दे रहे हैं। यह समर्थन सिर्फ सत्ता के लिए नहीं, बल्कि दीर्घकालिक साझेदारी का संकेत है।

राजनीतिक महत्व: युवा, तटीय वोट और सेकुलर फ्रंट

टीवीके की सफलता युवा और बदलाव की चाह पर टिकी है। कांग्रेस का 5 सीटों वाला समर्थन इसे स्थिरता दे रहा है। थारहाई जैसे चेहरे गठबंधन को तटीय और अल्पसंख्यक वोट बैंक में गहराई देते हैं। कन्याकुमारी जिले में टीवीके को रोकना कांग्रेस के लिए बड़ी जीत है।

विजय का मंत्रिमंडल 'कैबिनेट ऑफ फर्स्ट्स' साबित हो सकता है - युवा चेहरे, महिला प्रतिनिधित्व और सामाजिक समावेश।

थारहाई की नियुक्ति न सिर्फ कांग्रेस कार्यकताओं में उत्साह भर रही है, बल्कि पूरे राज्य में महिला सशक्तिकरण और मछुआरा समुदाय के विकास का संदेश देगी।

इतिहास की पुनरावृत्ति

थारहाई कुथबर्ट सिर्फ एक विधायक नहीं, बल्कि 60 साल बाद कांग्रेस की सत्ता वापसी की जीवंत मिसाल हैं। ळश्‍ड के उम्मीदवार को हराकर उन्होंने साबित किया कि स्थानीय जड़ें और समर्पण अभी भी काम करते हैं।

अब अगर वे विजय के मंत्रिमंडल में शामिल हुई तो तमिलनाडु राजनीति का नया अध्याय शुरू होगा, जहां सिनेमा का सितारा और कांग्रेस की 'मछुआरा बेटी' मिलकर राज्य को नई दिशा देंगे। यह गठबंधन सिर्फ सरकार बनाने का नहीं, बल्कि तमिलनाडु में सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण और युवा आकांक्षाओं का नया समीकरण है।